

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02/2019

**अपीलांट्स-**

1. रणछाराम पुत्र समेलाराम
  2. गणेशाराम पत्र समेलाराम
- जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना  
तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

**बनाम**

**रेस्पोंडेंट्स -**

1. हड़मानराम पुत्र प्रतापाराम जाति  
मेघवाल निवासी धोरीन्ना  
तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये  
तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध आदेश दिनांक 03.01.2019 जो तहसीलदार धोरीमन्ना मुकदमा  
सं. 2019/04 द्वारा पारित किया गया एवं इसकी पालना में दिनांक  
09.01.2019 को पैमाईश कार्यवाही रिपोर्ट।

**उपस्थिति :-**

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनिल के. मेराजा, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोंडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

**निर्णय**

दिनांक : 30/12/2019

अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रकरण  
सं. 2019/04 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2019 एवं उसकी पालना में  
पैमाईश कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी श्री हनुमानराम पुत्र  
श्री प्रतापाराम कौम मेघवाल निवासी धोरीमन्ना द्वारा मौजा धोरीमन्ना के  
खसरा नम्बर 366/2 रकबा 02-04 बीघा व खसरा नम्बर 426/09 रकबा  
00-12 बीघा में कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत करने पर  
तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/2019/04 दिनांक  
03.01.2019 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक धोरीमन्ना, भू-अभिलेख निरीक्षक बोर  
चारणान, पटवारी उड़ासर व पटवारी राणासर कल्ला की संयुक्त राजस्व टीम  
गठित कर निर्देशित किया गया कि मौके पर मय पुलिस इमदाद सहित  
विवादित स्थल का नियमानुसार माप कर शिकायत का निस्तारण करें। इस

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

आदेश की पालना में राजस्व टीम द्वारा दिनांक 09.01.2019 को विवादित भूमि की मौके पर पैमाईश कर मौका फर्द तैयार की गई। अपीलांत द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश दिनांक 03.01.2019 व उसकी पालना में की गई पैमाईश दिनांक 09.01.2019 की मौका फर्द रिपोर्ट के विरुद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांत के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष दिनांक 03.01.2019 को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 366/2 व 426/9 का सीमाज्ञान करवाया जाकर अपीलांत रणछाराम का कब्जा पाया जावे तो हटाने की कार्यवाही करावें। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उसी दिनांक राजस्व विभाग की टीम गठित कर सीमाज्ञान का आदेश पारित कर दिया जो कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई हैं। रेस्पोंडेंट द्वारा जिस भूमि का सीमाज्ञान करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है वह राजस्व की भूमि नहीं होकर आबादी की हैं, जिसकी पैमाईश व सीमाज्ञान का आदेश देने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं थे। रेस्पोंडेंट द्वारा सीमाज्ञान हेतु न तो कोई नियमानुसार प्रार्थना पत्र दिया और न ही शुल्क अदा किया गया। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा टीम का गठन कर पैमाईश का आदेश दिया गया है जो नियम विरुद्ध हैं। रेस्पोंडेंट के प्रार्थना पत्र पर सीमाज्ञान करने से पूर्व पड़ौसी खातेदारान को नोटिस दिया जाकर सुनवाई किये बिना उसकी गैर मौजूदगी में पैमाईश नहीं की जा सकती हैं तथा ऐसी पैमाईश रिपोर्ट महत्वहीन हैं। रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा खसरा नम्बर 426 की भूमि का रूपान्तरण करवाने के बाद भूखण्डों का निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक बेचान कर दिया है तथा अब वह पड़ौसी खातेदार की खसरा नम्बर 366/2 की भूमि हड़पने की नीयत से बार-बार पैमाईश करवा रहा है। इन सब तथ्यों की विधिवत जांच किये बिना की गई पैमाईश हेतु दिया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2019 निरस्तनीय हैं। इस आदेश की पालना में की गई पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 भी इस आधार पर ही निरस्तनीय हैं कि टीम द्वारा जिस मुस्तकील बिन्दु ए को मानकर पैमाईश की गई है वह खेती की माठ है, जिसे किसी भी दशा में मुस्तकील बिन्दु नहीं माना जा सकता हैं। रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा अपने हक-स्वामित्व से अधिक क्षेत्रफल का भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर दिया गया है तथा अब उन्हें भौतिक कब्जा दिलाये जाने



के लिये मौके पर कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर पड़ौसी खातेदार की खसरा नम्बर 426/9 की भूमि में नाजायज प्रवेश करने की गरज से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। अपीलांट के खसरा नम्बर 426/9 की यथास्थिति बनाये रखने हेतु माननीय सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.12.2016 को आदेश पारित किया है जिसके प्रभाव में रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं इसकी पालना में की गई पैमाईश की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 को निरस्त फरमाया जावे।


5. रेस्पोंडेंट सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौजा धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 02-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 426/9 रकबा 00-12 बीघा में कुछ लोग कब्जे बाबत झगड़े पर उतारू होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की शिकायत एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रस्तुत की गई थी। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौके पर हक-स्वामित्व के निर्धारण एवं कब्जे की जांच हेतु राजस्व विभाग के कार्मिकों की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें दो भू-अभिलेख निरीक्षक एवं दो अन्य हल्का के पटवारीयान को सम्मिलित कर निर्देशित किया गया कि उक्त विवादित स्थल पर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना के मध्यनजर मौके पर मय पुलिस इमदाद सहित नियमानुसार नाप कर शिकायत का निस्तारण करें। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्रशासकीय तौर पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्वयं के विवेकीय निर्णय द्वारा पारित किया गया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी सीमाज्ञान करने का निवेदन नहीं किया था बल्कि नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत की गई है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा विवाद का निपटारा करने हेतु दोनो ही खसरा की भूमि की पैमाईश करने के निर्देश दिये गये हैं ऐसे में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 366/2 एवं 426/9 में कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने से मौके पर झगड़ा होने एवं शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना बाबत शिकायत प्राप्त होने पर विवाद के निपटारा हेतु राजस्व विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर विवादित भूमि की पैमाईश करने का



आदेश जारी किया तथा इसकी पालना में टीम द्वारा दिनांक 09.01.2019 को पैमाईश कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांत द्वारा इस पैमाईश के आदेश एवं आदेश की पालना में की गई पैमाईश रिपोर्ट के विरुद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांत के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा अपने स्वामित्व से अधिक भूमि का हस्तान्तरण कर लेने मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं होने से पड़ौसी खातेदार की भूमि को हड़पने की नियत से सीमाज्ञान करवाया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या विवाद भूमि की सीमाओं को लेकर है तथा मौके पर की गई पैमाईश के फलस्वरूप यदि अपीलांत सीमा निर्धारण से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें नियमानुसार धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा विवादित भूमि के मौके पर कब्जे को लेकर झगड़ा होने तथा शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना के मध्यनजर जो अपीलाधीन आदेश दिया गया है उसके किसी प्रकार की अवैधानिकता की जाना प्रकट नहीं होता है। यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश से पूर्णतया सहमत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता है। अपीलांत यदि अपीलाधीन पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 के द्वारा किये गये सीमा निर्धारण से असंतुष्ट हैं तो वह नियमानुसार सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। इस प्रकार अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।
8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राकेश कुमार शर्मा)  
अपर जिला कलक्टर,  
बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

